सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कारखाने

27.93 **श्री रामगोपाल यादव** :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कुल कितने कारखाने हैं और इस समय उनमें से कितने कारखाने काम कर रहे हैं;

(ख)वर्ष 1987 से 1997 की अवधि के दौरान कुल कारखानों में से कितने कारखानों को बंद कर दिया गया;

(ग)क्या सरकार ने इन कारखानों को बंद कर दिए जाने के कारणों का पता लगाया है और संबंध में उचित कार्यवाही की हैं;

(घ)यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.)सरकार सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बंद पड़े कारखानों को पुनरूज्जीवित करने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहेगी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) 10

(ख)कोई नहीं।

(ग)प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को 1996 में औद्योकगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी0आई0एफ0आर0) को संदर्भित किया गया था। बी0आई0एफ0आर0 ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को ऑपरेटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निदेश दिया। बी0आई0एफ0असा0 ने ऑपरेटिंग एजेंसी द्वारा तैयार की गई मसौदा पुनरूद्वार योजना को दिनांक 2.6.98 को सभसी संबंधितों को उनकी टिप्पणियां देने के लिए परिचालित किया था।

VRS for PSUs

2794. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item "VRS for PSUs condemned by TUs" appearing in the "The Statesman" Calcutta dated the 15th June, 1998;

(b) whether employees with thirty years service form only one per cent of the workforce in the CPSUs, as reported;

(c) if not, the percentage of workforce in this category as per Government's estimate;

(d) whether circulars have been issued by Managements threatening suspension of operation in units unless employees opt for VRS;

(e) if so, the legal basis of such action; and

(f) if not, the name of the PSUs where VRS is being planned to facilitate closure of the units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) Yes Sir.

(b) and (c) Information relating to categories of workforce in PSUs based on number of years of service rendered is not readily available.

(d) to (f) No case of this nature has come to the notice of Government. Liberalised VRS package when offered will be open for a specific period within which the workers will be required to opt failing which they will be entitled to only retrenchment compensation statutarily admissible.

Development of Village and SSI in North East Region

2795. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the details of step, if any taken